



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2964]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2018/श्रावण 9, 1940

No. 2964]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2018/SHRAVANA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

**का.आ.3754(अ).**-केन्द्रीय सरकार के समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में **'बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में सेवा'**, में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 32 में आते हैं, को, जैसा कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.335(अ) तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तारीख 1 फरवरी, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था;

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास के लिए और विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 1 अगस्त, 2018 प्रभाव से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2016-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2018

**S.O. 3754(E).**— Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, *vide* number S.O. 335(E), dated 19<sup>th</sup> January, 2018 the services in the **‘Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka’** which is covered by item **32** of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) to be a **public utility service** for the purpose of the said Act, for a period of six months with effect from the 1<sup>st</sup> February, 2018;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the public interest requires extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares that the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, **for a period of six months with effect from the 1<sup>st</sup> August, 2018.**

[F. No. S-11017/1/2016-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.